feet deep, why should we get labour from outside? The people who are there locally must be able to do such jobs. We should insist that the project work of such a kind must be done by the people in the locality. It should be very easy. In fact, it should be done very easily and the people will be convinced about that.

Now, one of the mistakes that the Planning Commission did was this. There was a delay in excavation of field bothies in Hirakud. All of a sudden, it was found that there was no utilisation of the project, and there was a stampede. You were forced to take hasty action. There was a stampede with the result that you want to finance the excavation of the field bothies at Hirakud. That was a blunder. It should not have been done like that. That was one of the biggest blunders. it should not have been done like that. That takes away the self-reliance of the people. Excavation for field bothies has been done for centuries by the people. But we have not done that.

I submit that if we act with a certain amount of daring spirit and with a certain sense of urgency, I am sure it will be possible for the Planning Commission, a very high and intelligent body like the Planning Commission, to take proper measures for utilising the vast reservoir of people for the Constructive work.

Mr. Speaker: The hon. Member should conclude now.

Dr. K. L. Rao: I am concluding. I am very thankful to you for giving me a little more time. I would say that the Planning Commission, if it devotes itself to the formulation and the co-ordination work, which is most important and essential, can be of inestimable value and serve as a ladder by which we can mount up to the dizzy heights of the glorious days that were once India's.

17·26 hrs.

CHANGE IN DATE OF SITTING

Mr. Speaker: I have to inform the House that Muharram will be observed as a closed holiday on Thursday, the 14th June, instead of Wednesday, the 13th June, 1962, the sitting of the House presently fixed for the 14th June has been cancelled and a sitting has been fixed in lieu thereof on the 13th June, 1962.

Notices of question tabled for the 14th June will be treated as having been given for the 13th June, 1962.

17·27 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS—contd.

Ministry of Finance—contd.

Mr. Speaker: Any hon. Member from the Opposition that has not been represented in this debate?

श्रीमती सहोदराबाई राय : अध्यक्ष महोदय, इस तीन महीने के सेशन में मुझे अभी तक बोलने का कोई मौका नहीं मिला है . . .

अध्यक्ष महोदय : आप ने लिख कर भेज दिया होता । इस तरह से खड़े होकर कहना कुछ ठीक नहीं जंचता है ।

श्री रामेश्वरानन्द : श्रीमान्, मैं बोलना चाहता हूं । मैं एक मिनट के लिये पीछे चला गया था ।

अध्यक्ष महोदय : आपके ग्रुप का एक आदमी बोल चुका है ।

श्री रामेश्वरानन्द : वह तो केवल ५, ७ मिनट ही बोले थे ।

अध्यक्ष महोदय : आप अभी तो बठ जायें ।

मैं अपोजीशन ग्रुप्स से इस वक्त दरख्वास्त कर रहा हूं कि वे इस समय बोलें

लेकिन आज सब ग्रुप खामोश हैं और कल सब बोलना चाहेंगे । श्रीमती सहोदराबाई राय अब बोल लें ।

श्रीमती सहोदराबाई राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया । वित्त मंत्रालय ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करती हूं । इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि पिछले १४ वर्षों में हमारे वित्त मंत्रालय ने जो कार्य किया है वह सराहनीय है और बड़े अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी निबाही है । मैं समझती हूं कि कुछ भाइयों ने जो कांग्रेस शासन के खिलाफ कहा है तो ऐसा उन्होंने इस लिये कहा है कि उनको पूरी जानकारी नहीं थी । मेरे एक पूर्व वक्ता ने गाजीपुर और बलिया आदि के बारे में बोलते हुए कहा कि वहां पर खेतिहर मजदूर को दो आने मजदूरी मिलती है । यह बात उनकी गलत है । हिन्दुस्तान के अन्दर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कि दो आने मजदूरी मिलती हो । मजदूरों की मजदूरी आदि के बारे में मुझे पूरी तरह मालूम है । मेरे घर में खुद खेती होती है और इस नाते मुझे पूरी जानकारी प्राप्त है । सवा रुपये औरत को खेत पर मजदूरी करने का मिलता है । मर्द को डेढ़ रूपये मजदूरी मिलती है । गेहूं की बोनी जब होती है तो दो रुपया मर्द को मिलता है और डेढ़ पया औरत को मिलता है । चैत में जब गेहूं कटता है तो एक आदमी को गेहूं की कटाई में दस सेर की पूर या पांच सेर की पूर मिलती है ।

आजकल हालत यह हो रही है कि खेत पर काम करने के लिये मजदूर मिलते ही नहीं हैं । काश्तकार हमारे रो रहे हैं और कह रहे हैं कि जब से यह स्वराज्य आया है तब से हमारी काश्तकारी खत्म हो गई है क्योंकि खेत पर काम कराने के लिये मजदूर हमको मिल नहीं पाते हैं । बजाय देहातों में काम करने के वह शहरों की तरफ भागते हैं । उन्हें काश्तकार की तकलीफ का कोई ख्याल नहीं है और खेत पर कोई मजदूर काम ही नहीं करना चाहता है। शहरों में जाकर कोई बीडी बनाता है कोई होटल खोलता है तो कोई रिक्शा चलाता है तो कोई पान वगैरह बेंचने का धंधा करता है । इस तरह से काश्तकारी का काम बिल्कुल ठप्प है । दूसरी तरफ यही मजदूर इस बात का प्रोपैगंडा करते हैं कि हमें मजदूरी कम मिलती है । इस लिये यह बात बिल्कुल गलत है कि उन्हें मजदूरी दो आने मिलती है । माननीय सदस्यों को इस तरह के सुझाव देने चाहिये जिस से न गवर्नमेंट की हानि हो और न ही मजदूर दल की हानि हो। लेकिन इस तरह की गलत बात कहना कि दो आने मजदूरी मिलती है उचित नहीं है । हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कि मजदूर को दो आने मजदूरी मिलती हो । कहीं ढाई सेर अनाज मिलता है है तो कहीं कहीं तीन तीन सेर तक अनाज मिलता है । कहीं कहीं एक रुपया मिलता है । मेरे कहने का मतलब यह है कि मजदूरों की हालत पहले के मुकाबिले इन चौदह वर्षों में बेहतर हुई है । उनकी आर्थिक अवस्था सुधरी है । आज वह दोनों वक्त रोटी खाते हैं, और कपड़ा पहनते हैं । उनके पास जमीन है, बैल है, खेत है और गाय है । अच्छा पयजामा, कमीज, धोती, और पतलून वे पहनते हैं । आज जीवन की सब आवश्यकतायें उनके पास मौजद हैं और गवर्नमेंट के ऊपर यह लांछन लगाना कि हमारे पास कुछ नहीं है बिल्कुल अनुचित और गलत है । आजकल बड़े आदमी और मजदूर का तबका खुशहाल हैं अलबत्ता बीच का आदमी अपेक्षाकृत कुछ दुखी है और सरकार को उसके कष्ट व दुःख को कम करने की ओर ध्यान देना चाहिये ।

आज देश की सबसे बड़ी जरूरत नैतिकता की है । हमारे समाज में भ्रष्टाचार

[श्रीमती सहोदराबाई राय]

का बोल बाला है । अब होता यह है कि लेबरर्स में कुछ लोग जो कि मेहनत करके दसवीं या ग्यारहवीं कक्षा पास कर लेते हैं और नौकरी पाने के इच्छुक रहते हैं उनसे वे अफसरान जो ऊंचे ओहदों पर रहते हैं कहते हैं कि १०० रुपया लेकर आओ तब तुम्हें नौकरी मिल जायेगी । अब मैं यह नहीं कह ी कि जितने भी ऊंचे पदों पर सरकारी अफसरान हैं सब के सब बेईमान हैं और रिश्वतखोर हैं लेकिन इस तरह के अफसरान हैं जरूर जो कि प्राइवेट में उनसे इस तरह की नाजायज मांग करते हैं । इस तरह की शिकायतें अक्सर हमारे पास आती हैं और हम उनको बारे में जिम्मेदार अधिकारियों को लिखते भी हैं लेकिन सबूत के अभाव में कुछ हो नहीं पाता है । अब मरता क्या न करता । नौकरी के लिये जैसे तैसे अफसर की मुट्ठी गरम कर देता है । इस तरह की बहुत सी त्रुटियां हैं । हमारे वित्त मंत्री महोदय को सी० आई० डी० भेज कर सका पता लगाना चाहिये और इसको बन्द करने के लिये सक्रिय कदम उठाना चाहिये ।

कुछ भाइयों ने यह कहा कि हमा यहां पुल नहीं हैं, पाठशालायें नहीं हैं और सड़कें वगैरह नहीं हैं लेकिन मैं चैलेंज के साथ इस बात को कहती हूं कि हर जगह दो, तीन गांव के बीच में एक पाठशाला अवश्य खुली हुई है । गांवों में मिडिल स्कूल, हाई स्कूल आदि खुले हुये हैं । ऐसी कोई जगह नहीं है जहां स्कूल न हों । अब इसको मास्टरनी या मास्टर क्या करें अगर बच्चे ही घरों में पढ़ने के लिये पाठशालाओं में न आयें ? जब गांवो में शिक्षक लोगों के घ ों पर बच्चों को स्कूल भेजने के लिये जाकर कहते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि हमारा बच्चा खेती पर काम कर रहा है अथवा अन्य धं पर लगा हुआ है । वह बीड़ी बनाने का काम कर रहा है और वह स्कूल पढ़ने नहीं आ सकता है । अब आप ही बतलाइये कि वह बेचारे क्या करें जब बच्चों के मां बाप ही अपने लड़कों को स्कूल न भेजना चाहें तो क्या किया जाय? लेकिन जहां तक शिक्षा के प्रसार का सम्बन्ध है हमारे देश में शिक्षा का काफी चार हुआ है और पहले के मुकाबले बड़ी भा ी तादाद में लोग शिक्षित हुए हैं । हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई है कि हमारे लड़के और लड़कियां बी० ए०, एम० ए० पास कर के इंग्लैंड, जापान और अमरीका आदि से विशेष योग्यता की उपाधियां लेकर आती हैं और आज वे बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं आज उनमें से कितने ही एम० एल० एज और एम० पीज बन रहे हैं कितने ही बड़े बड़े डाक्टर्स और बैरिस्टर्स बने हुए हैं । जो तरक्की हमारे देश ने पिछले १४ वर्षों में की है वह अभूतपूर्व है और स्वप्न में यह खयाल नहीं था कि हमारा देश तनी तरक्की करेगा ।

श्री सत्य भामा देवी (जहानाबाद) : बहुत से लोग बेरोजगार भी हैं ।

श्रीमती सहोदराबाई राय : अगर बहन जी ज्यादा बी० ए० पास हैं, तो वह बाद में अपनी राय दे सकती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को चाहिये कि वह इधर ध्यान रखें ।

श्रीमती सहोदराबाई राय : अध्यक्ष महोदय, बहन जी बीच में न बोलें ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात आप मुझ पर छोड़ दें ।

श्रीमती सहोदराबाई राय : बेरोजगार वे हैं जो शराब पीते हैं, दम लगाते हैं, गुण्डई करते हैं, लुच्चे हैं, जो काम नहीं करते हैं । अगर वे ग़रीब और बेरोजगार न हों, तो क्या हों? देश ने हर एक क्षेत्र में तरक्की की हैं । देश में सडकें, पुल, बिजली के कारखाने, हवाई जहाज, रेलें आदि बनाई जा रही हैं और हर जगह मजदूरों को मजदूरी मिल रही है । आज कोई खाली नहीं है । अगर हम घर में

पलंग पर पड़े रहें और शराब के घूंट पीते रहें, तो गवर्नमेंट क्या करेगी । यह तो हमारा कसूर है । हमने देश को आगे बढ़ाना है और इस के लिये मिल-जुल कर काम करना है ।

जब मैं १९५५ में गोआ गई थी तो वहां की औरतों ने मुझ से शिकायत की थी कि हम को आठ आने मजदूरी मिलती है । मैं ने उन को कहा, "बहन जी, जब गोआ आजाद होगा, तो गोआ की तरक्की होगी"। माननीय सदस्य, श्री नाथपाई बैठे हैं । उन को मालूम होगा कि अब वहां पर क्या मजदूरी मिलती है । रुपया तो जरूर मिलती होगी । नहीं मिलती ? *(Interruptions)*

हमारे भाई, चाहे वह कांग्रेसी हों, सोशलिस्ट हों या जन संघी हों, जो भी सुझाव देते हैं, वह गवर्मेंट के खिलाफ देते हैं । में कहना चाहती हूं कि हम सब को राष्ट्र का निर्माण करना है । इसलिये अपने देश को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। जहां कमी हो, उस के बारे में हम वित्त मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करें कि इस प्रान्त में यह कमी है, इसलिये ऐसा कदम उठाये कि उस पूर्ति हो सके । मैं बारबार कहती हूं कि कई लोग ऐसा बोलते हैं, जिसका सिर न पैर । यहां पर सब को सोच-समझ कर बात कहनी चाहिये जनता ने माननीय सदस्यों को जिम्मेदारी से यहां भेजा है, इस देश का निर्माण करने के लिये भेजा है । इस लिये सरकार को सही सुझाव देने चाहिये और इस कार देश की हालत को सुधारने के लिये में सहायता देनी चाहिये ।

हम सब चाहते हैं कि हमारे गावों में अच्छी सड़कें बनें, हमारे यहां अच्छे अच्छे कारखाने खुलें, लेकिन पैसे का भी सवाल है । धीरे धीरे, शान्ति के साथ, सब काम होता जाता है । मैं वित्त मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करती हूं कि अब वह शहरों के कार्यों को छोड़ दें और देहात की तरफ़ बढ़ें जहां अब भी बहुत कमियां हैं, जहां हमारे लोग तक्लीफ में हैं । उन को ऐसा कदम उठाना चाहिये कि उन कमियों की पूर्ति हो और लोगों को शान्ति मिले ।

अभी माननीय सदस्य ने कहा कि गाजीपुर और बलिया वगैरह में से कम्यूनिस्ट और सोशलिस्ट जीत कर आते हैं। यह जीतने का सवाल नहीं है । यह दो आने मिलने का सवाल भी नहीं है । यह ो सोशलिस्ट और कम्यूस्टि ग़लत प्रचार करते हैं कि मजदूरों को दो आने मिलते हैं । कहीं भी दो आने नहीं मिलते हैं । वे लोग ग़लत प्रचार कर के चुनाव में जीतने की कोशिश करते हैं । हम कांग्रेसी लोग शान्ति वाले हैं । हम सब सहते हैं और उचित जवाब भी देते हैं । अगर हम दो चार सीटें हार भी गए, तो कोई बात नहीं है । अगर आज हम हार गए, तो कल फिर जीत जायेंगे । हम हमेशा के लिये थोड़े ही हार गए ?

मैं आज तीन महीने में पहली बार बोली हूं । मैं दूसरी दफ़ा लोक सभा में चुन कर आई हूं । मैं अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करती हूं कि वह महिलाओं को पहले मौका दें, क्योंकि उन को गृहस्थी का हाल ज्यादा मालूम है । महिलाओं को मालूम है कि घरों में क्या क्या होता है । अगर हमारे घर मे झगड़ा हो जाये, तो दो दिन सम्भालना मुश्किल है । दश की राजनीति को सम्भालना मुश्किल है ।

वित्त मन्त्री महोदय से मैं कहना चाहती हूं कि इस देश में रिश्वतखोरी बढ़ रही है । वह रिश्वतखोरी का पता लगाने के लिए सी० आई० डी० से काम लें और उसको रोकने के लिये कड़ा कदम उठायें । आज रिश्वतखोरी के कारण देश मे त्राहि-त्राहि है । वित्त मन्त्री महोदय ऐसे कदम उठायें कि देश के लोगों को शान्ति मिले और हम सब देश को आगे ले चलें । आज हर जगह

[श्रीमती सहोदराबाई राय]

गलतियां होने लगी हैं। वह जरा अपने कर्मचारियों को भी समझायें कि वे सोच-समझ कर कदम उठायें और जनता के साथ अन्याय न करें।

अध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आप को धन्यवाद देती हूं।

श्री रामेश्वरानन्द : वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्य वर्णम् तमसः परस्तात्। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय ।।

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,.....

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh (Parbhani): Is it supposed to be in order, Sir?

Shri Nambiar (Tiruchirapalli): Is it in order to have prayers like this?

Shri Nath Pai: It is recitation of a sloka.

Mr. Speaker: If he believes in that and everytime he has to begin his speech he invokes the blessings, I should not have any objection.

Shri Hari Vishnu Kamath: It is allowed in the House.

श्री रामेश्वरानन्द : मैं आपका ध्यान योजनाओं की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। जो काम योजनाबद्ध होते हैं, वे सभी सफल होते हैं। कदाचित् चोरी, जारी, व्यभिचार आदि काम भी योजनाबद्ध होने से सफल हो जाते हैं, परन्तु उनका परिणाम भयंकर निकलता है। इसलिये कोई काम सफल हो गया है योजनाबद्ध होने से, उससे यह न समझ लेना चाहिए कि हमारी योजना ठीक है।

आज देश की स्थिति विचित्र है। हमारी हजारों वर्गमील भूमि चीन से आक्रान्त है और पाकिस्तान सजग है। नेपाल के साथ भी हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे नहीं हैं। नागा पहाड़ियों में भी अभी विद्रोह आरम्भ है। देश के कोने कोने में पाकिस्तान आदि के गुप्तचर सजग हैं। इतने पर भी हमारे देश के शासक ऐसी योजनाओं में संलग्न हैं कि देश का क्या बनेगा, मैं नहीं समझता। इसलिये सरकार योजनायें बनाए, मगर वह निरपराध पशुओं को वध करने की योजना न बनाए, वह पक्षियों को वध करने की योजना न बनाए। जलचरों और स्थलचरों को भी जीने दिया जाये। यदि सरकार की भुजाओं में बल है, भगवान् ने उसको बुद्धि दी है, तो वह चीन से भारत-भूमि को रिक्त कराने की योजना बनाए, भारत-भूमि का स्वर्ग जो काश्मीर है, उसको पाकिस्तान से रिक्त कराने की योजना बनाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वामी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज वित्त मन्त्रालय के अनुदान जेरे-बहस हैं। इसलिये वे ऐसी बातें कहें, जिनका जवाब मिनिस्टर साहब दे सकें। अगर वह इस तरह की आम बातें कहना चाहते हैं, तो मैं उनको फिनांस बिल पर बोलने का मौका दे दूंगा। जो कुछ वह कह रहे हैं, उनका जवाब वित्त मन्त्री कैसे देंगे ?

श्री रामेश्वरानन्द : मेरा अभिप्राय यह है कि सरकार योजनायें बनाए और उन पर व्यय करे, मगर उन के साथ ये योजनायें भी जोड़ दी जानी चाहियें। वित्त मन्त्रालय और सारा प्रशासन इस प्रकार की योजनायें बनाए, जिससे देश का भला हो सके। अभी हमारे देश में ग़रीबी कम नहीं है। पिछले चुनावों में जिन लोगों ने अपनी राय दी है, उन में से लगभग ७५ प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं। सरकार इस प्रकार की योजना बनाए कि देश में कोई अनपढ़ न रहे।

आज कहा जाता है कि इतने स्कूल और इतने कालेज खोले गए हैं। मैं मानता हूं कि खोले गए हैं, मगर उन की स्थिति क्या है ? मैं आप को पंजाब की स्थिति बताना चाहता हूं। मैं अभी पंजाब के मुख्य मन्त्री को शिकायत लिख कर देकर आया हूं। करनाल में लड़-

कियों के चौदह हाई स्कूलों में मुख्याध्यापिकाएं नहीं हैं, स्कूलों में शास्त्री नियुक्त नहीं हैं, स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। इस सम्बन्ध में इतनी न्यूनताएं हैं कि उन को गिनाना एक प्रकार से कठिन हो जायगा। सरकार योजनाएं बनाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि वह मनुष्य बनाने की योजना बनाए। सरकार कैसा मनुष्य बनाना चाहती है ? सड़कें ऐसी हों, नहरें ऐसी हों, यह कहना तो ठीक है। वे होनी चाहियें। ट्यूबवैल भी होने चाहियें। मगर ये सब किस के लिये ? मनुष्य के लिये। और वह मनुष्य कैसा हो, जिसके लिये सब कुछ किया जा रहा है ? आज मनुष्य बनाने की योजना किसी योजना में भी सम्मिलित नहीं है। हम कैसे मनुष्य चाहते हैं, इसका वर्णन किसी भी योजना में मिलेगा नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार सड़कें और नहरें बनाए। वह और भी योजनायें बनाए। मगर प्रश्न यह है कि क्या किसी भव्य भवन में गधे को रख देने से वह श्रीमान् जी बन जाता है—नहीं वह कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता है। मेरा देश जिसको आप स्वर्ग बनाना चाहते हैं, इस स्वर्ग में रहने वालों का निर्माण आप करें। स्वर्ग में रहने वालों के निर्माण की जो भी योजना आप बना सकते हैं, बनायें। पहले युगों में जो भी योजनायें बनती थीं, उन में सबसे पहली योजना मनुष्य बनाने की बनती थी। यदि वह मनुष्य बन जाएगा तो सब कुछ ठीक कर लेगा, ऐसा समझा जाता था। यदि मनुष्य आपने अच्छा नहीं बनाया तो आप कितनी भी योजनायें बनाते चले जायें, कितना भी परिश्रम आप करते चले जायें, वह सारी योजना और वह सारा परिश्रम व्यर्थ जाएगा। पहले युगों में दो विशेष योजनायें होती थीं। एक तो मनुष्य बनाने की होती थी और दूसरे मनुष्यों को भी चार विभागों में बांटा जाता था। ये चार विभाग थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि। उन में कर्तव्यों का बटवारा कर दिया जाता था। ब्राह्मण का काम इतना ही होता था कि वह देखेगा कि कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। लेकिन आज मेरे देश में अध्यापक हैं, स्कूल हैं किन्तु फिर भी अनपढ़ता देश के अन्दर व्याप्त है और पर्याप्त मात्रा में लोग अनपढ़ हैं। आज योजनाबद्ध काम नहीं होता है।

दो ही तरह से आप देश का शासन चला सकते हैं, शस्त्र के द्वारा और शास्त्र के द्वारा। जब शास्त्र को कोई नहीं मानता है, जब शिक्षा को कोई नहीं मानता है तो हाथ जोड़ कर आप उसको कभी मना नहीं सकते हैं। सृष्टि के सबसे पहले राजा मनु हुए हैं। मनु ने अनेक नीति की बातें कही हैं। लेकिन उन्होंने एक सबसे बड़ी नीति की बात कही कि जो शिक्षा से न माने, उसको कैसे समझायें। उन्होंने कहा है :—

दण्डः शासति प्रजा सर्वः दण्ड स्वभि रक्षति
दण्डे सुपते सुजागृति दण्डं धर्मम् विदुर बुधः

जो किसी से नहीं मानता है इस दुनिया में वह डण्डे से मानता है। सर्कस में आपने देखा है कि जब बकरे को संकेत होता है तो वह शेर के सामने चला जाता है और जब शेर को संकेत होता है तो वह बहुत बड़ा मुंह खोल देता है और बकरा उसके पास जाकर उसके मुख में अपना सिर रख देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह शेर क्या हाथ जोड़ने से उस बकरे को दांत नहीं लगने देता। नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। शेर अहिंसक नहीं हो जाता है, महात्मा गांधी का शिष्य नहीं हो जाता है या उसने योग शास्त्र नहीं पढ़ लिया होता है। वह हण्टर के डर के कारण, विद्युत् के डंडे के डर के कारण उस बकरे के सिर को तो क्या, उसके सिर के बाल तक को दांत नहीं लगने देता। इसलिये दुनिया में जो.....

Shri Namblar: Sir, is all this connected with the Finance Ministry's Demands? From the Plan he has gone to circus.

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी, मैंने पहले ही आपको इसके बारे में बताया था :

श्री रामेश्वरानन्द : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी योजना संक्षिप्त नहीं है। यह बहुत विस्तृत है। आपको समझने का यत्न करना चाहिये। आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो मेरा क्या अपराध है?

मे नेष: स्थानोरपराध: यदे नम् अन्धो न पश्यति

मैं योजना से बाहर की बात नहीं कह रहा हम जो यहां बैठे हैं, यह भी योजना है, जो बोल रहे हैं, यह भी योजनापूर्वक बोल रहे हैं, खाते पीते भी हम योजना-पूर्वक हैं, कपड़े भी योजना पूर्वक पहनते हैं। जो योजना शब्द है, यह बहुत विस्तृत है। हमारे जितने कार्य होते हैं, छोटे से छोटे कार्यों से लेकर बड़े से बड़े कार्यों तक वे सारे के सारे योजनाबद्ध रीति से होते हैं। मैंने शुरू में ही संकेत किया था कि डाकू लोग जो डाके मारते हैं, वे भी योजनाबद्ध होते हैं तभी वे अपने प्रयत्नों में सफल होते हैं। इसलिये योजना को आपको समझना चाहिये। दुनिया में जब किसी को आप किसी अन्य तरीके से नहीं मना सकते हैं तो डंडे से मना सकते हैं बालक जब आपका कहा नहीं मानता है तो उसके कोमल कपोलों पर दो परमिट काट जब दिये जाते हैं तो वह सीधा हो जाता है और स्कूल चला जाता है। पशु और पक्षी सब के सब इस डंडे के सहारे काम करते हैं। घोड़े में इतनी चाल कैसे आ जाती है, बैलों में इतनी चाल कैसे आ जाती है, ये सारे काम योजनाबद्ध होते हैं।

इसलिये मैं चाहता हूं कि आपकी योजना हो परन्तु योजना केवल नाचने की न हो, पशु पक्षियों के वद्ध की न हो, लड़के लड़कियों को उलटी बातें सिखाने की न हो। जो योजना आपने चला रखी है उसमें सबसे पहले मनुष्य बनाने की योजना होनी चाहिये। शिक्षा बहुत ही उत्तम उनको दी जानी चाहिये। मैं ऐसे क्षेत्र से आया हूं जो ६०-७० मील लम्बा है। वहां पर इसी वर्ष केवल एक हायर सेकेंडरी स्कूल खुला है। सारे क्षेत्र में यमुना के तट से लेकर एक ही स्कूल खुला है। इसलिये आप की योजना बहुत ही उत्तम होनी चाहिये। इन्ही योजनाओं के आधार पर ऋषियों ने जिस समय राजा अश्वपति से पूछा कि आपके राज्य का क्या हाल है, तब उन्होंने एक ही श्लोक में सब कुछ कह दिया कि मेरे सारे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई जार नहीं है, कोई मांसाहारी नहीं है, कोई शराबी नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है, कोई परस्त्रीगामी पुरुष नहीं है और कोई परपुरुषगामी स्त्री नहीं है। यह सब शिक्षा के आधार पर हुआ।

मैं यहां पर डंडे के बारे मे अधिक कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन आज हो क्या रहा है। आज हमारे देश में योजनाओं के होते हुए भी, पुलिस के होते हुए भी, सेनाओं के होते हुए भी डाके आए वर्ष पहले से ज्यादा पड़ते हैं, आए वर्ष की अपेक्षा कत्ल अधिक होते हैं, व्यभिचार, अन्याय और अत्याचार ज्यादा होते हैं। इन सब बुराइयों में निरन्तर वृद्धि ही हो रही है।

मैं यह सब कुछ इसलिये नहीं कह रहा हूं कि मैं जनसंघ की टिकट पर चुन कर आया हूं। लेकिन आप पुरानी फाइलें उठा कर देख लें, पुलिस की फाइलें उठा कर देख लें, किसी भी विभाग की फाइलों को उठा कर देख लें, यह चीज आपको प्रत्यक्ष नजर आ जाएगी। झूठी प्रशंसा की जाए, यह हम से नहीं हो सकता है। ऐसा मैं करने के लिये तैयार नहीं हूं। व्यर्थ किसी की झूठी प्रशंसा नहीं की जानी चाहिये। मैं आपको एक प्राचीन बात बतलाना चाहता हूं। महाराजा युधिष्ठिर के राज्य में चीन का राजा भगदत्त ईरान का शल्य, अमरीका का ववरुवहन, यूरोप का विड़ालाक्ष, सभी बलि (कर) लेकर आये थे। आप महाभारत को उठा कर और उसको पढ़ कर देख लें। किस आधार पर वे आए थे। योजना के आधार पर व डण्डे के आधार पर आये थे। मेरा हृदय घबराता है यह कहते हुए कि दूसरे यह कहते हुये कि दूसरे देशों और देशांतरों के लोग हमारी योजना से सम्बद्ध हैं। अगर आज कहीं अवसर उपस्थित हो जाये युद्ध का तो मैं देखता हूं कि मेरे देश का सब

कुछ होते हुये भी, कौन हमारी सहायता करेगा, उस युद्धाग्नि में कौन पड़ोसी देश, कौन मित्र देश हमारा साथ देगा । इसको छिपाया जा नहीं सकता है और न ही छिपाया जाना चाहिये । मैं तो मानता हूं :—

पुरुषा वहवो राजन्
सततं प्रिय वादिनः
सत्य सेतु पथ्यसे श्रोता
वक्ता च दुर्लभः ।

बहुत व्यक्ति हैं जो सदा प्रिय बोलते हैं, खुशामद की बात करते हैं परन्तु सत्य भी हो और हितकर और लाभदायक भी हो, ऐसी बात कहने वाले बहुत थोड़े व्यक्ति हुआ करते हैं । मैं यह नहीं कहता कि हमने कोई उन्नति नहीं की । मैं मानता हूं कि हम ने कुछ सड़कें बनाई हैं, कुछ उन्नति की है, कुछ ट्यूबवैल बनायें हैं, नहरें बनाई हैं । लेकिन दुःख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मेरा देश जो एक समय सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज विदेशों के ऋणों के नीचे दबा हुआ है । इस चीज को छिपाया नहीं जा सकता है । आप योजन बनायें लेकिन वैसी योजना नहीं जिससे भारत वैसा ही बन सके, जैसे वह पुराने जमाने में बना हुआ था, वैसा भारत वर्ष बन सके जैसा कि वह पुराने जमाने में संसार के सामने बना हुआ था । आज मेरे घर में कलह है, आज जमीदार और गैर-जमीदार, मालिक और मजदूर के बीच एक विवाद उठ खड़ा हुआ है, आज बैकवर्ड और गैर बैकवर्ड का विवाद उठा खड़ा हुआ है, आज कारखाने के मालिक और कारखाने में कान करने वाले मजदूर के बीच विवाद उठा खड़ा हुआ है । कुछ पार्टियां यत्न करती हैं, लोगों को भड़काने का । मगर क्या हम इस प्रकार की योजना बना सके हैं जिससे इनका विवाद शांत हो, जिससे देश एक हो सके, ब्राह्मण से लेकर हरिजन तक देश के सभी लोग मिल जुल कर काम कर सकें । ऐसा हम नहीं कर पाये हैं और मैं चाहता हूं कि इस लक्ष्य को सामने रख कर हम काम करें और इस भारतवर्ष को पुराना भारतवर्ष बनाने की कोशिश करें ।

Mr. Speaker: Hon. Members may now move their cut motions relating to the Demands under the Ministry of Finance subject to their being otherwise admissible.

Policy towards developmental programmes in the country

Shri Sivamurthi Swami: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (3).

Need to strengthen the financial autonomy of States

Shri M. K. Kumaran: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (57).

Need to change the budgetary system so as to make budget under standable to layman

Shri M. K. Kumaran: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (58).

Need to bring about stability in prices

Shri Surendranath Dwivedy: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (59).

Failure to take measures against persons or companies violating foreign exchange regulations

Shri Surendranath Dwivedy: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (60).

Need for introduction of cost accounting in the Public Sector Undertakings

Shri Surendranath Dwivedy: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (61).

Failure to raise internal and external resources for the Plan

Shri Surendranath Dwivedy: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (62).

Difficulties created consequent on the cut in the American aid

Shri Surendranath Dwivedy: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (63).

Need to improve the working of the Reserve Bank of India

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (64).

Need to improve the working of the Agricultural Credit Department of the Reserve Bank of India

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (65).

Need to improve the working of the Refinance Corporation

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100. (66).

Need to improve the working of Industrial Finance Corporation

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (67).

Failure to check malpractices in the Banks

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (68).

Need to improve the working of the Rehabilitation Finance Corporation

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (69).

Need to improve the working of Income-Tax Department

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (70).

Need for reorganisation of tax collecting machinery

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (71).

Failure to collect arrears of taxes

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (72).

Need for launching prosecution against the tax defaulters

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (73).

Need to check tax evasion

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (75).

Failure to curb malpractices in the General Insurance Companies

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (76).

Need for nationalisation of General Insurance

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (77).

Failure to check the upward trend of prices of consumer goods

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (78).

Need for a rational policy for opening Branches of the Banks

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (79).

Need to check the smuggling of gold

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (80).

Need for abolition of Contractor Cashier system in Reserve Bank of India

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (90).

Need for restriction on bringing of foreign officers in Private Commercial Undertakings

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (91).

Need for change in advance policy of State Bank of India

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (92).

Failure to check smuggling of watches in India

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (93).

Failure to check tax evasion

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (94).

Need for centralised sales tax system all over the country

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (95).

Need for improvement of the service condition of field workers in L.I.C.

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (96).

Failure to implement the recommendation of the Joint Committee for field workers in L.I.C.

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (97).

Policy for the promotion of class II and class I officers of Income Tax Department

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (98).

Need for change in the loan policy of L.I.C.

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (99).

Need for stringent control over advance policy of Banks

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (100).

Need for opening more branches of Reserve Bank of India

Shri Prabhat Kar: I beg to move:

"That the Demand under the head Ministry of Finance be reduced by Rs. 100." (101).

Need to recognise the Civil Accounts Staff Association, Shillong, Assam

Shri Nambiar: I beg to move:

"That the Demand under the head Audit be reduced by Rs. 100." (81).

Relationship of staff with the Accountant General in Shillong

Shri Nambiar: I beg to move:

"That the Demand under the head Audit be reduced by Rs. 100." (102).

Fear of insecurity prevailing among the staff of the Accountant General's Office in Shillong

Shri Nambiar: I beg to move:

"That the Demand under the head Audit be reduced by Rs. 100." (103).

Review of the punishments imposed on the staff of the Accountant General's Office, Shillong during the last one year

Shri Nambiar: I beg to move:

"That the Demand under the head Audit be reduced by Rs. 100." (104).

Need to pay dearness allowance to pensioners getting below rupees 250 as pension

Shri Sivamurthi Swami: I beg to move:

"That the Demand under the head Pensions and Other Retirement Benefits be reduced by Rs. 100." (7).

Failure to plan balance development of different parts of the country

Shri M. K. Kumaran: I beg to move:

"That the Demand under the head Planning Commission be reduced to Re. 1." (82).

Failure to take into account the claims of Kerala in locating Public Sector enterprises

Shri M. K. Kumaran: I beg to move:

"That the Demand under the head Planning Commission be reduced to Re. 1." (83).

Need to provide money for developing Paradip as a major port during the Third Five Year Plan

Shri Surendranath Dwivedy: I beg to move:

"That the Demand under the head Planning Commission be reduced by Rs. 100." (84).

Need to take adequate measures to remove regional disparity

Shri Surendranath Dwivedy: I beg to move:

"That the Demand under the head Planning Commission be reduced by Rs. 100." (85).

Need for priority in the matter of industrial and agricultural development

Shri Surendranath Dwivedy: I beg to move:

"That the Demand under the head Planning Commission be reduced by Rs. 100." (86).

Demand of the States to revise plan allotment and for introduction of new schemes.

Shri Surendranath Dwivedy: I beg to move:

"That the Demand under the head Planning Commission be reduced by Rs. 100." (87).

Need to give Central assistance to the Kerala State for anti-sea-erosion work

Shri M. K. Kumaran: I beg to move:

"That the Demand under the head Grants-In-Aid to States be reduced by Rs. 100." (88).

Need to disburse grants with a view to minimise social and economic disparities in different States and regions

Shri M. K. Kumaran: I beg to move:

"That the Demand under the head Grants-In-Aid to States be reduced by Rs. 100." (89).

Need for adjustment of all loans and advances given to the State of Mysore in respect of Gold Mines, being nationalised

Shri Sivamurthi Swami: I beg to move:

"That the Demand under the head Loans and Advances by the Central Government be reduced by Rs. 100." (15).

Mr. Speaker: These Cut motions are now before the House.

श्री तुलसीदास जाधव: (नांदेड़) : अध्यक्ष महोदय, आज इस फाइनेन्स डिमान्ड पर बोलते हुये बड़ा सन्तोष होता है । अगर देश की आर्थिक उन्नति की दृष्टि से देखा जाय तो हम बहुत बड़ी तेजी से आगे बढ़े हैं । उत्पादन की दृष्टि से देखा जाय तो हमारे पास जो थर्ड फाइव इयर प्लान की बुक है उस के पेज ३५ पर जो आंकड़े दिये गय हैं उन से पता चलता है कि देश का उत्पादन इतनी तेजी से बढ़ा है और इतनी तेजी से उन्नति हुई है कि उस से अधिक नियोजन करने में इस देश के अन्दर जो शासन करने वाली पार्टी है उस के फाइनेन्स निमिस्टर यशस्वी हुये हैं । देश के अन्दर उत्पादन तो बढ़ना ही है लेकिन वह किस रीति से बढ़ना चाहिये जिस से कि देश की एकनामिक परिस्थिति की ऊंच नीच में समता आ जाये ? इसका एक ही उपाय है जिस को कहते हैं सोशलिस्टक पैटर्न आफ सोसायटी । इस के रास्ते पर और इस के ध्येय को ले कर हमें जाना है । सन् १९५६ का जो इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन है उस में यह बतलाया गया है कि इस देश में जो चीज लानी है उस को एक दम से लानाहै । आज कल जब हम दूसरे देशों के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ४५ साल होने के बाद भी रूस में पूर्णतया सोशलिज्म नहीं आ पाया है । वहां डिक्टेटरशिप आफ प्रोलेटेरिएट होते हुये भी जब मैंने १९५१ में रूस को देखा था तो ३५ वर्ष बाद भी वहां दरिद्रता नजर आती थी । जब मैंने देहातों में जा कर वहां के लोगों को देखा तो उन के अंगों पर फटे हुये कपड़े थे, उनकी बैलगाड़ीं टूटी फूटी थी, कई मकान जो थे वे भी ऐसे वैसे थे जैसे कि अपने यहां के कई कई जगहों पर होते हैं, जब कि वे भी अधिक नियोजन कर रहे हैं । तो ४५ वर्ष तक डिक्टेटरशिप आफ प्रोलेटेरिएट होते हुए भी, वहां पर दूसरी

[श्री तुलसीदास जाधव]

पार्टी न रखते हुए भी, वहां से दरिद्रता मिट कर समता नहीं आई है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जो आर्थिक समता लानी है, जो सोशलिज्म लाने की हम कोशिश करते हैं, अगर उसे हम लोग लोक शासन के तरीके से करना चाहते हैं तो वक्त लगना लाजिमी बात है ।

दुनिया भर के जो अलग अलग उत्पादन के आंकड़े हैं उनको देखने के बाद अगर पता लगाया जाये तो पन्द्रह वर्षों में हिन्दुस्तान ने जितनी उन्नति की है, उतनी उन्नति किसी भी देश ने की हो, ऐसा नजर नहीं आता है । मैं ज्यादा आंकड़े तो नहीं बतलाना चाहता लेकिन कल्पना के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना के पृष्ठ ३६ पर जो क्राप्स के इंडक्स दिये हैं उनको उद्धृत करना चाहता हूं :

ग्रुप	१९५०–५१	१९५५–५६	१९६०–६१
आल क्राप्स	९६	११७	१३५
फूड क्राप्स	९१	११५	१३२

यानी जो भी क्राप्स का इंडेक्स नम्बर है उसमें हर जगह पर बढ़ोतरी हुई है । सवाल उठता है कि जब अनाज ज्यादा बढ़ता है तो कमी क्यों होती जाती है ? उस की एक ही वजह है कि हमारे यहां पापुलेशन भी बढ़ती जाती है । उसके लिये खास तौर से विचार करना होगा । इतनी पापुलेशन बढ़ते हुए भी आज कल देहातों में, जैसा मेरी सम्मानीय बहन ने अभी कहा, ऐसी बात नहीं है कि किसी को उद्योग नहीं मिलता । हमारे प्रान्त में देखा जाये तो देहातों में मजदूर मिलते ही नहीं हैं । दो दो, ढाई ढाई रुपया रोज देते हुए भी आज मजदूर नहीं मिलते , यह बात सही है । स्टैंडर्ड आफ लिविंग बढ़ गया है । दोनों बातें आज दिखलाई पड़ती हैं । स्टैंडर्ड आफ लिविंग बढ़ जाने पर भी जो उत्पादन होता है उसका जो पैसा मिलता र वह मंहगाई के अनुरूप नहीं है । उत्पादन और डेवलपमेंट दोनों ही तेजी से बढ़े हैं लेकिन फिर भी ऐसी बात दिखलाई नहीं देती है ।

अब आप इंडेक्स नम्बर आफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखिये :

ग्रुप	१९५५–५६	१९६०–६१
जनरल इंडेक्स	१३९	१९४
काटन टैक्सटाइल	१२८	१३३
आइरन ऐंड स्टील	१२२	२३८
मैशीनरी।आलटाइम्स	१९२	५०३
केमिकल्स	१७९	२८८

मैं इससे अधिक आंकड़ों में नहीं जाना चाहता । इसको देखने से यह खयाल आता है कि देश में उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है और देश के अनएम्प्लायमेंट में भी थोड़ी कमी हुई है, साथ ही लोगों के रहन सहन में कपड़े के मामलों में और प्रवास के सम्बन्ध में भी एक प्रकार के लोगों को जदा से ज्यादा सहूलियत मिली है, यह बात सही है ।

इस देश में अगर आर्थिक नियोजन की दृष्टि से देखा जाये तो उसमें कई बातों की कमी भी है । अगर उन कमियों को दूर कर दिया जाये तो जो दिक्कतें इस सम्बध में होती हैं वह कम हो जायें । अगर आर्थिक नियोजन की दृष्टि से देखा जाये तो उसमें कोई खराबी हो, ऐसी बात नहीं है । मालूम यह पड़ता है कि इस देश में लोगों को जो अपेक्षायें हैं वह बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और यह बात सही है कि उन अपेक्षाओं के अनुसार हमारा आर्थिक नियोजन और देश का आर्थिक पाया आगे नहीं बढ़ता है । लेकिन कल्पना से और मस्तिष्क से सोच कर आगे जाने में समय तो लगता ही है । स्वराज्य मिलने से पहले हम लोग कहा करते थे कि स्वराज्य के बाद हम लोग ऐसा प्रयत्न करेंगे जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें मिलेंगी । लेकिन यह बात सही है कि आज लोगों को जो अपेक्षा है उस अपेक्षा के अनुसार

हम सहूलियतें लोगों को नहीं दे पाये हैं । फिर भी हमको यह सोचना चाहिए कि हमें जो भी उत्पादन करना है उसे तो डिमाक्रेसी के तरीके से करना है, लोगों को समझा बुझा कर करना है, और ऐसा करने में टाइम लगता ही है । अगर इस दृष्टि से दुनिया भर के आंकड़ों का मुकाबला यहां के आंकड़ों से किया जाय तो हम पायेंगे कि हिन्दुस्तान सब से आगे है ।

जो हमारे सेन्ट्रल गवर्नमेंट के फाइनेन्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी यहां पर बजट रखा और उसमें टैक्स को बढ़ाया । उसके बाद में अपने यहां के तीन चार जिलों में घूमा । मैंने देखा कि देहातों में जो खेडूत लोग हैं उनको मालूम नहीं होता है कि टैक्स बढ़ गया है । मैंने कई जगहों पर मीटिंगें बुला कर लोगों से पूछा कि क्या तुमको मालूम हुआ कि अब की जो बजट रखा गया है उसमें कुछ बढ़ाया गया है । उन्होंने जवाब दिया कि उनको कुछ नहीं मालूम पड़ा है कि क्या कर बढ़ाया गया है । यानी करों को आपने इतना सोच विचार करके बढ़ाया है कि लोगों को मालूम नहीं हुआ है कि कर बढ़ाये गये हैं । लोगों को अपने रहन सहन के सम्बन्ध में ज्यादा तकलीफ न हो, इस तरीके से बजट के अन्दर टैक्स बढ़ाये गये हैं । मैंने व्यापारियों और दूसरे लोगों को बुलाया और कहा कि मर्सराइज्ड कपड़े पर टैक्स बढ़ाया गया है । सभी ने इस बात को कबूल किया कि जो टैक्स बढ़ाया गया है उसमें कोई ज्यादा असन्तोष नहीं है। इसके यह मानें हैं कि इस बजट में जो भी टैक्स बढ़ाये गये हैं उनका गरीब आदमियों पर कोई अधिक असर पड़ा हो या उनको मालूम हो कि टैक्स बढ़ने से उनकी तकलीफ ज्यादा बढ़ गई हो, ऐसी बात नहीं है ।

हां, कुछ बातों में लोगों की तकलीफ बढ़ गई है, उन को मैं बड़ी नम्रता से अपने फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के सामने रखना चाहता हूं । वह बात यह है कि हमारे प्रान्त में, यानी महाराष्ट्र में जो पावर लूम्स हैं, उनके ऊपर टैक्स ज्यादा बढ़ने से कई कई जगहों पर पावर लूम्स बन्द होने के रास्ते पर हैं । यह धंधा महाराष्ट्र में ही ज्यादा है । पावर लूम्स को कपड़ा बनाने के लिये जो मिल का सूत लेना पड़ता है उसके लिए दूना दाम देना पड़ता है । उदाहरण के लिये एक धोती जोड़ा जिसकी साइज़ ९ गज ४५ इंच है उसके बनाने में मिल में चार रुपये का सूत लगेगा लेकिन उसी के बनाने में पावर लूम पर वही चार रुपये का सूत आठ रुपये में मिलेगा । तो इस तरह से सूत का दूना दाम देना पड़ता है ।

16 hrs.

इधर के प्रान्तों का हाल तो मुझे नहीं मालूम लेकिन हमारे यहां इच्छल करंजी मिरज, शोलापुर, भिवंडी और मालगांव आदि जगहों में हर घर में दो दो तीन तीन पावर लूम हैं चलते हैं अभी तक दो पावर लूम्स पर एक्साइज ड्यूटी नहीं थी । अब चार पावर लूम्स पर एक्साइज ड्यूटी माफ की गई है । लेकिन ५ से २४ पावर लूम पर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है यह पहले से तीन गुना कर दिया गया है इससे लोगों को तकलीफ होती है मैंने सुना है कि एक प्रतिनिधिमंडल फाईनेन्स मिनिस्टर साहब से मिला है और यह अच्छी बात है कि उन्होंने इस विषय पर फिर से विचार करने का आश्वासन दिया है मैं भी हाउस में यह प्रार्थना करता हूं कि इस पर फिर से विचार अवश्य किया जाऐ पहले सन् १९६१ में चार पावर लूम्स पर साढ़े १२ रुपया टैक्स था । और पांच से लेकर ९ पावर लूम्स पर २५ रुपये एक पावर लूम को ८ घंटे की पारी में महीने भर चलाने के लिए था । अब उसको बढ़ा कर ४५ रुपया कर दिया गया है यानी एक लूम पर २० रुपया ज्यादा बढ़ा दिया गया है । दस से २४ लूम्स पर पहले २५ रुपया प्रति लूम था जिसको बढ़ा कर अब

[श्री तुलसीदास जाधव]

६० रुपया कर दिया है। यानी प्रति लूम ६५ रुपया बढ़ा दिया गया है। इससे पावर लूम चलाने में बड़ी कठिनाई हो रही है। और मेरा निवेदन है कि इस पर फिर से विचार किया जाए। पहले जो २१ लूम्स पर टैक्स देना पड़ता था उससे अब १४ हजार रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। इस काम में इतना प्राफिट नहीं है और लोगों को यह टैक्स अपने घर से देना पड़ता है। इसलिए लोग बड़ी कठिनाई में हैं।

अभी हाल में मैं जब दौरे पर गया था तो लोगों ने मुझ से कहा कि और बाकी चीजें तो ठीक हैं लेकिन यह पावर लूम्स पर इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया है कि हमको चलाने में मुसीबत हो गयी है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मिनिस्टर साहब इस मामले पर विचार करें। मेरा कहना है कि देश में सोशलिज्म तभी आ सकेगा जब कि उद्योग का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाए। यह पावर लूम्स पर जो टैक्स बढ़ाया गया है यह बहुत ज्यादा है और इसलिए लोग अपने लूम्स को बेचने का विचार कर रहे हैं। लेकिन मैं ने सुना है कि उनको बेचने भी नहीं दिया जाता। बेचने से भी उन के ऊपर टैक्स माफ नहीं होगा। तो यह भी देखना चाहिए। जिनके पास २५ लूम्स हैं वे लोग टैक्स ज्यादा होने के कारण उनको बेच कर चार चार लूम चलाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा करने से भी टैक्स माफ नहीं होता। तो यह बड़ी मुसीबत है।

देश के अन्दर तीन प्रकार से इंडस्ट्री चल रही है, पब्लिक प्राइवेट और कोआपरेटिव। तीन तरह से काम चल रहा है। अगर सोसाइटी भी चार से ऊपर लूम चलाती है तो उस पर भी टैक्स माफ नहीं है। तो मेरा कहना है कि जो लोग कोआपरेटिव सोसाइटी से चलाते हैं उनको कुछ सहूलियत मिलनी चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि देश आर्थिक दृष्टि से तेजी से तरक्की कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। लेकिन कई जगह पर बड़ी तकलीफ भी है। मैं अपने शहर शोलापुर के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। शोलापुर शहर में एक शोलापुर स्पिनिंगएण्ड वीविंग मिल है। उसकी बड़ी दुर्दशा है। उसमें तीन हजार मजदूर काम करते हैं। मालूम नहीं पड़ता कि उसमें मेनेजमेंट की और सरकार की दोष का कितना हिस्सा है लेकिन वह मिल ठीक से चलती नहीं है। परसों जब मैं दिल्ली आ रहा था तो कोई तीन चार सौ कामगार मेरे घर पर आए और उन्होंने कहा कि हमें रोजाना काम नहीं मिलता इसका इन्तिजाम किया जाए, न ठीक कपास मिलता है और न ठीक से काम चलता है"। उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इन कामगारों को ठीक से काम मिल सके। लेकिन गवर्नमेंट को इस मिल को देखना चाहिए और जिस तरह सरकार एक और दूसरे मिल को अपने अधिकार में ले कर चला रही है उसी तरह इसको भी चलाने पर विचार करे ऐसी मेरी प्रार्थना है।

कुछ सज्जनों ने कहा कि रूस में मजदूर की तनख्वाह ज्यादा है और जो अफसर हैं उनकी तनख्वाह कम है। मैं उनसे विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मैं रूस में एक महीने रहा हूं और गांवों में घूमा हूं और इकानामिस्टस से चार चार घंटे तक चर्चा की है। मैं ने देखा कि वहां तनख्वाहा में काफी फर्क है। जो पगार मजदूर को, स्कूल टीचर और क्लर्क को मिलता है उससे बहुत ज्यादा तनख्वाहा अफसर को मिलता है। पगार में कई गुना तक का अन्तर है। मैंने यह तलाश किया तो मालूम पड़ा कि उनका मतलब सोशलिज्म से यह नहीं है कि पगार में अन्तर न हो, जहां तक मैं समझा हूं उनका मतलब सोशलिज्म से यह है कि कोई अपने पैसे के कारण किसी का एक्सप्लायटेशन न कर सके। उदाहरण के लिए एक आदमी चार कारें रख सकता है लेकिन ड्राइवर नहीं रख

सकता, चार बंगले रख सकता है लेकिन उन को किराए पर नहीं उठा सकता। अपना रुपया ब्याज पर नहीं चला सकता। वह अपने पैसे का उपयोग अपने लिए कर सकता है लेकिन उसका किसी दूसरे का एक्सप्लायटेशन नहीं कर सकता। तो इस तरह से वहां काम चलता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वहां से यहां की तुलना नहीं की जा सकती। आप देखें कि वहां मंहगाई बहुत ज्यादा है। यहां का २०० रुपए का पगार और वहां का एक हजार का पगार बराबर होगा। वहां एक साबुन का दाम यहां से चार पांच गुना है। इस चीज का अध्ययन मैं ने लन्दन आदि कई जगहों पर किया है। और मैं ने यही समझा है कि रूस में सोशलिज्म का यही अर्थ समझा जाता है कि इस तरह से काम किया जाए कि कोई आदमी अपने रुपए के कारण दूसरे का एक्सप्लायटेशन न कर सके। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि जो आदमी गटर में काम करता है उसको अफसरों से ज्यादा पगार मिलता है। हम अपने देश में डिमानेसी के द्वारा सोशलिस्ट पैटर्न की तरफ चल रहे हैं और यह अच्छा है और मुझे आशा है कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब अपने कैबिनेट के सहयोगियों द्वारा इस दिशा में सही मार्ग अपनाने में सफल होंगे।

इतना ही मुझे कहना है।

Shri S. M. Banerjee: Mr. Speaker, Sir, many points have been made in this House regarding foreign exchange position and other things. I would confine myself to three or four points. My first point—I have been forced to repeat it in this House—is about the general strike of 1960. I am sorry to bring his particular point to the notice of the hon. Minister and I have to do it because the comptroller and Auditor General fortunately or unfortunately enjoys a constitutional touch-me-not position in our country. This is the only opportunity when I can bring these cases to the knowledge of the hon. Minister. In almost all the departments, whether it is the Posts and Telegraphs, Railways or Defence, those employees whether temporary or permanent who were suspended, discharged or dismissed from service, have more or less been taken back. Those who have not yet been taken back have a chance and I am sure within a month or so they are likely to be taken back. But there are about 33 or 34 cases of temporary employees and 11 permanent employees who belong to the audit department, in Shillong, Simla, Kerala and in other parts of the country who have not yet been taken back. Some Members of Parliament met the Auditor-General and he suggested to them recently that those employees should express regret and then their applications would be considered favourably. They expressed regret and eight of them, whom I know personally, have sent their applications long ago. But unfortunately nothing happened. I would urge upon the hon. Finance Minister to consider these cases and impress upon the Auditor-General, if he can, to take them back into service.

It may be mentioned in this House that none of the employees took part either in sabotage or in violent activities. They also did not come under the Essential Services Act. So, I am sure that their cases will be treated according to the pronouncement of the late-lamented Home Minister, Pandit Govind Ballabh Pant, namely, those people who merely participated in the strike will not be dealt with severely. I am sure those cases will be settled.

With the Home Minister's announcement regarding restoration of recognition, in almost all the departments, whether it is a federation of association or union, those bodies got back their recognition. But under the Auditor-General, these are three associations of audit employees and staff in Simla, Kerala and Bombay. In respect of those bodies, the recog-

[Shri S. M. Banerjee]

nition has not been restored. I would like to know whether the Auditor-General is capable of flouting the Home Minister's order which has been respected by almost all the Ministers and ministries. I would, therefore, request the hon. Finance Minister to consider this matter a bit more seriously.

Then there is the question of Shillong. The association of audit employees there is still to get its recognition restored. It was first withdrawn. They demonstrated peacefully, rather they did not demonstrate as such but they went collectively for the redressal of their grievances and they wanted to meet the Accountant-General. That was the only crime committed by them, and they lost their recognition and today, in Shillong, nearly 200 employees have been charge-sheeted and disciplinary proceedings have been taken against them on minor, flimsy grounds. I am sure that their cases will be settled and that in Shillong the recognition would be restored.

Recently, the Auditor-General has given certain conditions; one of them is that they should abide by constitutional methods; that t hey should not do anything which embarrasses the officers. The association concerned has given in writing that it would abide by the constitutional methods, and I am sure that the hon. Finance Minister will kindly look into their cases also and restore recognition to the association as early as possible.

18.14 hrs.

[SHRI MULCHAND DUBE *in the Chair*]

Then I may refer to the insurance employees. The insurance employees have given their charter of demands. I am happy that the Chairman of the Corporation is dealing with the employees in a very congenial atmosphere. I have no grouse against that. But I was surprised to know that in Chandigarh a class IV employee working in the Life Insurance Corporation has to pay Rs. 22 per mensem as house rent. This was something surprising. When I met the Divisional Manager, he told me that this matter has been taken up at the highest level. He was unable to do anything nor could the Zonal Manager do anything unless the Chairman of the Corporation and the Government of India intervened in the matter. I cannot imagine a class IV employee of the LIC paying Rs. 22 a month as house-rent when the same employee under the Central Government in Chandigarh is only paying 10 per cent of his basic salary as house-rent. I would request the hon. Finance Minister to kindly see that this is reduced to 10 per cent or Rs. 7 or Rs. 8 whichever is less.

Then I come to the question of the field employees of the Life Insurance Corporation. Sir, a Committee was appointed and that committee recommended payment of bonus also. But I am surprised to find that these field employees have been deprived of this bonus. The argument advanced is that because they are entitled to advance increment they will not be given this bonus. I am really sorry that this decision has been taken even after the unanimous recommendation of that particular Committee which comparised of the employees' representative and the representative of the Life Insurance Corporation. I would request that this matter should be considered very seriously and sympathetically, and they should also be given bonus.

Then comes the question of income-tax. I am not concerned with evasion because I do not know what is the amount of evasion. Nobody knows in this country. According to Professor Kaldor it was to the tune of Rs. 300 crores or Rs. 400 crores. According to the Finance Minister the amount has been reduced to Rs. 200 crores or Rs. 150 crores. But when the question of recovery of income tax comes it is always said that the effective arrear is being reduced. My hon. friend Shri Prabhat Kar said some-

thing about effective arrears, and he maintained that the amount is Rs. 250 crores. It may not be Rs. 250 crores, and according to the Finance Minister effective arrears is to the tune of Rs. 130 crores or Rs. 131 crores. Anyhow, the amount is not being recovered.

Sir, when I refer to this question of recovery of income-tax I have before my eyes the Kanpur cases. In 1957, when I raised this question of recovery of income-tax, wealth-tax and gift-tax, the answer came from the hon. Finance Minister that the total amount was Rs. 4.98 crores or nearly Rs. 5 crores. Though it has been reduced to Rs. 2.70 crores, I would like to know from the Finance Minister why this huge amount has accumulated and why this is not being recovered. I would like to know what positive steps have been taken to announce the names of those who are doing all sorts of tricks to evade income-tax when the country needs so much of finance for the success of the Five Year Plans.

Next comes the question of sales-tax. When I say sales-tax, I know the hon. Minister may say that it is a State matter. But the sales-tax procedure is so complicated that an ordinary shopkeeper is unable to maintain proper accounts and with all his sincerity and honesty there is said to be some evasion of sales tax.

Shri Morarji Desai: Sales-tax has nothing to do with us. What is the use of saying it here. I have no authority.

Shri S. M. Banerjee: There are Central Sales Tax Officers.

Mr. Chairman: I think the best thing would be to confine ourselves to the subject.

Shri S. M. Banerjee: Sir, may I refer only to sales-tax cases concerning the Delhi Administration? It will become a central subject. What I want to say is, the procedure is very cumbrous. I would request the Finance Minister to kindly see that some simple method is found so that the shopkeepers are able to maintain their accounts and at the same time clear their sales-tax.

With regard to the taxation policy, Sir, my hon. friend Shri Lahri Singh mentioned something about the new taxes in Punjab. I would only refer to the professional tax. The State Government might have the professional tax.

Shri Morarji Desai: What has that to do with the Demands of the Finance Ministry here?

Shri S. M. Banerjee: Every Central Government employee today has to pay all these things. In a memorandum the Central Government employees have written to the Central Government and State government that this should not be levied on them.

Mr. Chairman: Central Government employees, where?

Shri S. M. Banerjee: Central Government employees in the Punjab in the Punjab. They have to pay the professional tax.

Shri Morarji Desai: That is no ground for discussing it here on the Demands of the Finance Ministry.

Shri S. M. Banerjee: When we are discussing planning and so many other things, I think this can also be discussed. Sir, I seek your protection. When Shri Lahri Singh was speaking on all these things, practically everything found on this earth, he was allowed to speak about them under these Demands.

Mr. Chairman: That is hardly an argument. The point is whether what my learned friend is saying is relevant to the subject before the House or not. The objection of the hon. Finance Minister is that it is not relevant.

Shri Nambiar: May I submit that the other day during his speech the hon. Finance Minister said that the States must bring forward more taxation otherwise they cannot deal with the needs of the Plan? He has therefore given an invitation rather to increase taxation and we can also refer to such taxes which are being brought in by the States at his request or incitement.

Mr. Chairman: Even then it would be a State subject. It would not become a Central subject.

Shri Morarji Desai: May I say that that was discussed in the general debate? Now there is no question of a general discussion. Today it is on the Finance Demands, a particular Demand. Therefore it cannot be talked about. That is my view.

Shri S. M. Banerjee: I agree with him. So, I need not refer to the taxation in Punjab, but as a whole in the country there is a movement going on against taxation. In Punjab I seek the protection of the hon. Finance Minister against the threat issued by the Chief Minister of Punjab to the effect that he is going to crush all political parties and individuals.

Shri Morarji Desai: I support the Chief Minister in recovering those taxes.

Shri S. M. Banerjee: Surely, he will support him, but he should not send the Army there. That is what I say. I am only saying that the Central Government employees are liable to transfer from place to place and I request the hon. Finance Minister to consider whether they should also pay the professional tax which is hard on them.

Shri Morarji Desai: They should.

Shri S. M. Banerjee: Then I am going to refer to certain recommendations of the Pay Commission. I hope that it comes under the Centre. What is hapenning in Simla? Previously the Central Government employees in Simla were paid compensatory allowance according to the Simpla Code. They have suffered as a result of the Pay Commission's recommendation. Their allowances have been reduced. They submitted a joint memorandum to the hon. Finance Minister on behalf of all Central Government employees that if these allowances could not be increased at least the *status quo* should be maintained and they should be given compensatory allowance according to the Simla Code. That is a thing which I am sure will be taken as an anomaly arising out of the implementation of the Pay Commission's Report and the hon. Finance Minister will kindly see to this.

The there are certain recommendations of the Pay Commission. The Pay Commission's Report was published some time in 1959. I think it was in November, 1959. We were assured in this House that almost all the recommendations had been accepted by Government and that these recomendations would be implemented. There were only some modifications in the Report which were also accepted ultimately. But there are many recommendations like leave to the industrial employees in Defence and other undertakings which have not yet been implemented. So, I would request the hon. Finance Minister to see that the remaining recommendations of the Pay Commission which have been accepted by the Government of India are implemented without any delay, otherwise these Pay Commissions recommendations have no value.

My hon. friend, Mr. Hanumanthaiya, suggested the appointment of another Pay Commission which should consider the pay scales of all, right from the President to an ordinary man. This was his suggestion, I believe. I do not say whether that Pay Commission will ever submit its report when this Pay Commission submitted its report after two years and we had to spend Rs. 10,74,000 on it, but I would surely sugest that a Pay

Commission should be appointed for teachers and other employees who were not covered by that Pay Commission. It is high time that we appoint that sort of a Pay Commission.

Then there is the question of holding the price line. Whenever we raise this question about holding the price line in the House, whenever we say that prices are going up, we are immediately told that prices are not going up and wholesale prices are quoted in this House. I submit that wholesale prices have no relation to retail prices in this country. If the hon. Finance Minister wishes to know the retail prices in each place, he will find that the difference between the retail price and the wholesale price is so much that it warrants that prices should be stabilised somewhere. The anticipation of the First Pay Commission was that the prices would be stabilised at 165 to 175 points. Unfortunately prices have not stabilised. As against this the Central Government servants have been granted a dearness allowance ranging from Rs. 5 to Rs. 15, inspite of the fact that prices are going up. I would request the Finance Minister to kindly keep this particular point in view and take immediate steps to see that prices are stabilised.

One more word and I have finished. When I speak of taxation, I may remind the hon. the Finance Minister that there is a growing feeling in the country about taxation and there is an agitation going on in almost all the States. I know that the agitations would be crushed. That is a different matter, but the feeling of the common man that in spite of the success of the First two Plans and the promotion of the Third Plan, whether he is born only for the Plans or whether he would derive any benefits out of the Plan. If they are convinced that the Plans are for them and the success of the Plan would bring them definite relief they would work for their success. Taxation has reached saturation point. I would request the Finance Minister to look into this aspect.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: Mr. Chairman, Sir, Paul Haufman a distinguished economist said that the sixties are the most crucial decades and they are the most dangerous as well. In fact, we are feeling the impact of his observation when we see the Finance Minister reducing the level of limit of income-tax to Rs. 3,000. I remember, Sir, the first Finance Minister, James Wilson made a proposal that incomes above Rs. 2,000 should be liable to taxation, and I will not be surprised if our Finance Minister goes to the level of taxing incomes to the tune of Rs. 2,000. History after hundreds of years has taken a complete turn. We are in the sixties. We are thinking of levying income-tax to the level of Rs. 2,000, while we know that Rs. 2,000 is no appreciable level of income.

As regards economic working Prof. Galbraith has something to say about conventional wisdom when he said: "Maximisation of the returns and maximisation of employment should be the true criteria for efficient economic working". So far as maximisation of returns is concerned, we have the debacle of the rate of growth at 3.5 per cent per annum—rate of growth in income I mean. The increase of population is to the tune of 2 per cent. We have increased taxation by 14 per cent per annum and with this our increase of income of 3.5 per cent sounds ridiculous. The back-log of employment continues to grow. Even after the end of the First and the Second Plans this is assuming astronomical heights. We feel that the unemployment problem has to be tackled at a national level. From the purely economic point of view we have somewhat failed in the matter of maximisation of employment.

We feel that money supply which stood in 1958 at Rs. 28.8 crores has increased to Rs. 128 crores in 1959;

[Shri Shivaji Rao S. Desmukh]

In 1960 our money supply has gone up to Rs. 246 crores. Therefore, if the sectors of our economy have to develop faster and work efficiently and produce the maximum results we have to put in maximum efforts, not merely efforts at imposition of taxation, but also efforts at collection of taxation, efforts at removal of evasion of taxation and efforts at collecting non-tax incomes. So far as non-tax incomes are concerned, we have to remember that States have almost no avenues of non-tax income.

We see in this country the spectacle of 72 public concerns where investments are to the tune of Rs. 700 crores, yielding Rs. 3.62 crores by way of profits. This is hardly 0.51 per cent. Only this day we have heard from the Commerce Minister that the public undertakings under his Ministry are earning a uniform profit of 15 per cent. We have also heard from another Minister that in certain Corporations like the State Trading Corporation our profits are 40 per cent. So, if the profits in some concerns are 40 per cent and in many 15 per cent, and still you find the spectacle of 0.51 return on our national investments, it is certainly a very sorry state of affairs, and something has to be done to improve this state of affairs.

So far as profits are concerned, 10 per cent of the limited companies account for 46 per cent of the capital. Giant companies, that is companies with an investment of Rs. 1 crore as capital or more are about sixty. More or less they control 50 per cent of the investment. The top ten business firms in this country have doubled their capital since 1950 to 1960, and they together account for 67 per cent of the capital investment.

This concentration of wealth in the hands of a few is certainly not the picture of socialistic pattern of society on which the people have voted us to power. The people have voted us to power with hopes definitely.

I agree with the Finance Minister when he says that patience is the last item to be taxed. This country has almost inexhaustible funds of patience. But can any one with impunity dare to tax the patience without having a revolt or what may be called strong opposition against such tax incidence? But man cannot live by hope alone, and people cannot be fed by hopes of a prosperous life. That prosperous life and the image of India which we want to place before the masses has to assume some day or other a concrete form.

If we see the picture here in India we find that 85 million agricultural labourers have a *per capita* income of 27 naye Paise a day which is hardly the cost of three Capstan cigaretes. We expect in this poor country an agricultural labourer to live on 27 naye Paise per day. No less an authority than Dr. Chandrasekhar has stated, perhaps in Calcutta, that 10 crores of people in this country do not get what may be termed as one square meal a day according to the American standards—never in their lifetime.

If this is the standard of our development, our Finance Ministry deserves drastic improvement. And if there is one person who can improve the Finance Ministry, I have no doubt that it is the present Finance Minister. But he has to show his talents in a more brilliant and more daring way. And we wish good luck to him.

Shri Nambiar: By imposing more taxes.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: Possibly yes.

Shri Morarji Desai: You won't do anything better.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: So far as efforts at tax collection are concerned, we see in this country the unhappy spectable of the Centre making all-out efforts for tax collection and the States evading their responsibility so far as tax collection is

concerned. We have seen that the dependence of the States on the Centre for financial purposes has increased so much that the provincial autonomy which we speak of from the housetops, in financial or economic terms or in respect of dependence on the Centre, has proved meaningles. And with this increased dependence of the States on the Centre, the States will be mere subsidiaries or appendages growing on the Centre. Something drastic has to be done to push up the tax-collecting efforts of the States.

Where the tax-collecting efforts are concerned,we have seen the spectacle of the Third Finance Commision taking a positive step towards discouraging tax collection by States at the maximum eqort. Because, our Third Finance Commission was bold enough to recommend certain financial grants-in-aid to the States to meet their revenue deficit. But revenue deficit is because of the anxiety or the worry of the States to levy fresh taxes. If the States do not levy fresh taxes, the Finance Commission comes to their rescue by making good the revenue deficit which will accrue to the States. This recommendation of the Finance Commission is accepted by the Finance Ministry. With the result that States are further discouraged from making great tax efforts. In this respect, I wish to point out that there has been a definite injustice done to the State of Maharashtra. Maharashtra can modestly claim to be a financially better administered State. Maharashtra can modestly claim honest sincere efforts towards tax collection. It has no appreciable revenue deficit, not because it does not want to develop, not because its demands and requirements for development are less, but because Maharashtra goes by conservative wisdom of Finance administration wherein the revenue deficit should be the minimum. What is the result? The result is, Maharashtra State has been singled out by the Finance Commission and they have refused any grant for it in the form of recommendation and this recommendation has been accepted at the Centre. The result is, Maharashtra State which can honestly claim to make honest efforts towards maximisation of tax collection, suffers at the hands of the Finance Commission and through that at the hands of the Finance Ministry at the Centre. Therefore, if something has to be done to boost up the tax collection of the States, States like Maharashtra which have placed their financial adminstration in the hands of experts rather than in the hands of politicians, States like Maharashtra which are honestly administered financially, which go by conventional wisdom, should not be punished, should not be allowed to be punished by the Finance Ministry. Something has to be done to revise the recommendations of the Finance Commission and allow the State of Maharashtra certain grants over and above the recommendations of the Finance Commission.

So far as the State of Maharashtra is concerned, the argument thrown at our face is that Maharashtra is a forward State. We have no accepted yardstick for gauging the backwardness or forwardness of a State. Maharashtra, certainly, by any standards, is not a forward State even compared to the most backward State like Assam. For instance, the total road mileage, which has something to do with the prosperity of the State, the position is this. Maharashtra has 3,070 miles.

	Route miles per 100 sq. miles	Miles per Vehicle
Maharashtra	19	1
Bihar	48.9	4.2
Kerala	56.5	2.6

Shri K. N. Tiwary (Bagaha): What is the per capita income of Bihar and Maharashtra?

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:

Shri Morarji Desai: That is because, there are many more vehicles in Maharashtra.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:

West Bengal 63.6.

Here, I should add that the national average is 21.3 miles per 100 square miles. Maharashtra has much below this.

Shri K. N. Tiwary: Route mileage is not the only criterion for the backwardness or forwardness of a State.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: Route mileage is supposed to be evidence of prosperity or well being or backwardness of a State. I wish to lay stress on the route mileage particularly from this point of view that by way of another recommendation of the Finance Commission, certain grants have been reserved for development of communications, and even in that chapter, Maharashtra has been neglected by omission. Not a single naya paise has been recommended towards the development of communications by the Third Finance Commission to the Maharashtra State. This also is a positive injustice which, though not inflicted by the Finance Ministry, is tolerated by the Finance Minister, I should say, resourceful Finance Minister.

Therefore, we wish that something should be done in order to augment the resources of the Maharashtra State. Maharashtra's finances have suffered from three largest setbacks in the near past. First is the bifurcation of bi-lingual Bombay. Because of bifurcation of bi-lingual Bombay, net cash was transferred to Gujerat. We do not say that it is any favour. The net result has been that Maharashtra's finances have been completely smashed; they have been depleted. See the spectacle of the Panshet disaster. One disaster of that sort would have been enough to wash off the strongest economy of any State in this country. But we have seen that in spite of the Panshet disaster, Maharashtra's economy is trying to struggle; it has not succeeded, but it is only trying to struggle. In that struggle, if the Centre does not come to its rescue, it will be only unfortunate.

I say that Maharashtra has taken the most revolutionary step of transferring certain avenues of income to the districts, with the result that every district council in Maharashtra has got Rs. 2 to 4 crores worth of budget, but the result on the State's finances, and its financial administration has gone worse, because a part of the Maharashtra Government's finances and certain avenues of taxation by the State have now been transferred to the district councils. And Maharashtra has to run its administration with very little sources of tax collection. Therefore, in this respect also, Maharashtra has got a very sympathetic case for consideration at the hands of the Finance Ministry.

Maharashtra has got three peculiar problems. It is not that Maharashtra's stnndard of living or *par capita* income is above the all-India average. It is much less than that. Maharashtra has got seven districts which are known as scarcity districts, and these scarcity districts have got their own problems which are to be tackled not at the State level but, I should say, at the national level. So far as the scarcity districts are concerned, they are Ahmednagar, Sholapur, Poona, Satara, Aurangabad, Bhir and Osmanabad. The population affected is 34,16,259, and the area involved is over 17,000 square miles. In these scarcity areas, there is failure of the crops, almost a total failure of the crops in a good length of period. A scarcity and famine survey conducted by the State of Maharashtra says that in 32,005 square miles area, affecting 5,09,770 people, there is total failure of crops every three years, that is, once in three years. In the case of another classified area, where there is almost a total failure once in six years, the area involved is 5,741 square miles, and it affects 11,04,042 people. In certain other areas, where there is total failure of crops, or almost a total failure of crops once in ten years the area involved is 8,068 square miles, affecting a population of

18,02,447. These scarcity areas are a permanent backlog on the economy of Maharahstra, and these scarcity areas are so only because of lack of water, and only because the irrigation requirements of Maharashtra have been neglected by the Centre. No sufficient aid has been forthcoming for the uplift of these scarcity area. No schemes for the irrigation of these scarcity areas are forthcoming and if they are forthcoming, they are relegated by the Centre and not supported by the Centre financially.

The *per capita* expenditure of individuals in these scarcity areas is Rs. 12.15 per month. Can we imagine a man living for one full month on a paltry sum of Rs. 12.15? While the *per capita* expenditure of individuals in the entire State of Maharashtra does not exceed Rs. 15.46, at least slightly less than half of the total population of the scarcity areas just expend only Rs. 10 per month, and more than three-fourths expend Rs. 14 per month. 'Beg, borrow or steal' is what is usually said. But they cannot spend more than Rs. 10 per month at all. How could they exist then?

Certain more intensely scarcity areas have been further neglected by the Central Government, and no consideration has been paid for the backlog on Maharashtra's economy and the efforts needed, which Maharashtra alone cannot put forth, not for uplifting these areas, but for bringing them somewhere near the national level.

Then, Maharashtra has also got the Konkan, which is supposed to be an inaccessible part of India, and the most backward type of region in the whole of India. The Government of India had appointed an Inaccessible Areas Committee, and that committee has had something to say about Ratnagiri district. They say that Ratnagiri district is having a length of 300 miles and a breadth of barely 45 miles, and according to the 1951 census, had a population of 17.12 lakhs, of whom 90 per cent live in villages. Able-bodied persons of the district have been transported to Bombay as industrial workers resulting in a big socio-economic problem in the district. Ratnagiri will be the only district in India where the percentage of females to males would be the highest, 122 females per 100 males.

Shri Morarji Desai: Because the men are in Bombay.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: They are in Bombay because they have nothing to eat in Ratnagiri. Something should be done for Ratnagiri so that they could comfortably live there. They have not gone to Bombay for a favour, but out of necessity.

Shri Morarji Desai: They send money orders to Ratnagiri.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: The Inaccessible Areas Committee says in its report:

> "Forces of nature and mankind have successfully conspired and acted jointly for the last two centuries in reducing countryside to a state of wilderness, leaving in it the very minimum possible potentiality for food production. The inaccessibility of this area, though pronounced, ranks second to the local problem of depleted production potential through prolonged soil erosion."

The Committee says that problems of areas like Ratnagiri should be dealt with on a national basis and special provision should be made in additional normal provision in the Third Five Year Plan.

We have seen that the Centre not only caters for the developmental needs of a State but for its extra plan expenditure. Maharashtra, because it does not undertake any extra plan expenditure involving an appreciable amount, is also the victim, and it does

[Shri Shivaji Rao S. Deshmukh]

not get any financial aid which other States get under one pretext or other. This also will have to looked into.

Maharashtra has got most backward areas like Vidarbha and Marathwada.

Mr. Chairman: The hon. Member's time is up.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: I will continue tomorrow.

Mr. Chairman: He may take a minute or two more and conclude.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: We feel that Maharashtra's genuine case for increased financial assistance, even if that means setting aside certain recommendations of the Third Finance Commission, stands on sheer merits and have to be sympathetically considered. As of right, we can claim that Maharashtra has been singled out for injustice, and that singling out has been, though not with the connivance of the Finance Minister, at least with his consent. Therefore, we feel that something must be done for increased aid to Maharashtra.

Now we are talking so much about non-tax incomes. I have an idea. There is an industry called the stevedore industry in India. The stevedores were the invention of the Britishers. When the Britishers could not get local labour for handling port traffic, the Stevedore Institute came into being 200 years ago. Now according to the Vasist Committee, appointed by the Government of India, the net income of a stevedore per ton of cargo handled is approximately Rs. 2—Rs. 1.75 to be exact. I have got figures for 3 ports which are governed by the scheme of Dock Boards. These Dock Boards are there for arranging labour required by the shipping agents. The stevendore play no role, or next to nothing, in labour supply. These stevedores with the help of one telephone and one clerk manage to earn millions. If the Government pay their attention towards nationalisation of this stevedore industry, the net income to the State exchequer will not be less than Rs. 15 crores. The Calcutta port handles 35,029,528 tons of cargo.

Shri Morarji Desai: We are discussing Finance Demands, not Transport Demands.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: I am putting this in the light of nationalisation.

Calcutta, Bombay, Madras, Cochin, Visakhapatnam and Kandla together handle 77,689,766 tons. So at the rate of Rs. 2 per ton handled, the net profit to the exchequer will be Rs. 15,53,79,532. The cost involved in this taking over will be next to nothing. The benefits to the workers will be something substantial. With this amount of Rs. 15 crores per annum at our disposal, we can make a significant addition to our tax receipts. Therefore, I would request the Finance Minister to look into this question of nationalisation of this industry and do the needful.

18.50 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

SECOND REPORT

Shri Rane (Buldana): Sir, I beg to present the Second Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Chairman: The House stands adjourned to meet at 11 o'clock tomorrow.

18.51 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, June 12, 1962/Jyaistha 22, 1884 (Saka).